



**दृष्टि....** (पेज एक का शेष) उत्सव 'शुरू होगा।' उन्होंने आगे कहा, "आप अपनी पसंद की वस्तुएं ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे... इससे गरीब, मध्यम वर्ग, नव मध्यम वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, व्यापारी और दुकानदार लाभान्वित होंगे।" मोदी ने कहा कि ये होलोग्राफ़ के लिए सभी को बधाई दी। मोदी ने कहा, 'ये सुधारों को गति देंगे कारोबारी सुधारों को बढ़ाएंगे और अधिक निवेशकों को आकर्षित करेंगे।' प्रधानमंत्री ने जब जब 2017 में जीएसटी ने 'एक राष्ट्र-एक कर' के सपने को साकार किया। मोदी ने इस बात को उल्लेख भी किया कि कैसे करों और टाल के जाल ने व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए कठिनाइयां पैदा की हैं। उन्होंने 12 लाख रुपये तक की आय पर अयकर छूट और जीएसटी सुधारों का हवाला देते हुए कहा कि यह गरीबों, नव-मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए दोहरा लाभ है। उन्होंने कहा कि इन दोनों फेसलों से छोटे और मझे उद्यमों (मेयरसमैट) को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी सुधारों से खोदेशी सामान बेचने और खरीदने में गर्भ महसूस करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि खोदेशी आदोलन की तरह, भारत की समृद्धि भी स्वदेशी के मंत्र से मजबूत होगी। जीएसटी सुधारों के लागू होने से रसोई के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, दवाओं और उपकरणों से लेकर ऑटोमोबाइल तक, लगभग 375 वस्तुओं पर दरें सोमवार से घट जाएंगी। उपभोक्ताओं को एक बड़ा तोहफा देते हुए, केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की दरें कम करने के फैसला किया था। मोदी ने अपने 19 मिनट से ज्यादा के संबंध में कहा कि संशोधित जीएसटी दरें उनकी सरकार के 'नागरिक देवो भवः' के मंत्र के दर्शकों हैं, क्योंकि इससे रोजगरी की जरूरत की वस्तुओं के दाम कम होंगे और निर्माण एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में स्वर्च में कटौती होगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भारत के सूक्ष्म, लघु और कुटुर उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उन्होंने देश में ही यथासंभव विनिर्माण का आवान किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विकल्पों को लेकर अधिक जागरूक होने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विदेशी मूल की वस्तुएं अनजाने में लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है, और उन्होंने लोगों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में उद्योग जगत की आग्री पूछताएँ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि रोजमर्झी की जरूरत के खाद्य पदार्थ, दवाएं, साबुन, मजन, टूथप्रॉप्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा या तो—मुक्त होंगे या उन पर केवल पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के रखें वही बचे हैं। उन्होंने कहा कि रोजमर्झी की जरूरत के खाद्य पदार्थ, दवाएं, साबुन, मजन, टूथप्रॉप्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा या तो—मुक्त होंगे या उन पर केवल पांच प्रतिशत कर दायरे में आती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से नागरिक और व्यापारी करों के एक जटिल जाल में उलझे हुए थे। मोदी ने 2014 में पदमार्ग ग्रहण करने के तुरंत बाद एक विदेशी समाचार पत्र में पढ़ी एक खबर का जिक्र किया, जिसमें लिखा था कि एक परिवारी को करों की अधिकता के लिए उत्तरांशी की दूरी पर बैंगलुरु से हैदराबाद तक दाम पहुंचाना और उत्तरांशी को यूरोप भेजने और फिर वापस हैदराबाद लाना की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्यों सहित सभी दित्तधारकों के साथ मिलकर उनकी वित्ताओं को दूर करने और 2017 में 'एक राष्ट्र-एक कर' लागू करने के लिए उन्हें सहमत करने का काम किया।

**विशेष अनुष्ठान...** (पेज एक का शेष) प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के योगदान से छोटे-छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। शाह ने कहा, 'इस तरह, एक दिन हम निश्चित रूप से उनके (दिव्यांगों) लिए एक अच्छी जीवन और करियर सुनिश्चित कर पाएंगे।' गृह मंत्री ने दिव्यांग सुनुदाय से जुड़े मुद्दों के समाधान और उनके प्रति नजरिया बदलने के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। साल 2015 में 'विकलांग' शब्द की जगह 'दिव्यांग' शब्द इत्तेमाल किया गया, जिसका अर्थ है दिव्य शरीर। शाह ने कहा, 'शब्द के इस एक परिवर्तन ने लोगों और सरकारों के वृद्धिकोण को बदल दिया।' उन्होंने कहा, 'हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिसके तहत यह सुनिश्चित करना समाज की जिम्मेदारी हो कि दिव्यांग राष्ट्र निर्माण में योगदान दें और जीवन में आगे बढ़ें।'

**युवा नशे...** (पेज एक का शेष) में इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के बाद सोमवार के आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे ले जा रही हैं। माझी ने युवाओं से शराब, धूम्रपान या नशे की लाज से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि यह न केवल एक व्यक्ति को बर्बाद करता है बल्कि परिवारों को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा, 'नशे की लत पढ़ाई में असफलता, स्वास्थ्य पर बुरा असर और आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है। नशे में भूबा युवा अपने माता-पिता के सपनों को चकनाचूर कर समाज और देश के लिए बोझ बन जाता है।'

**विशेष अनुष्ठान...** (पेज एक का शेष) के बाद सोमवार से समलैंश्वरी मंदिर में नवरात्रा पूजा शुरू होगी और नौ दिनों तक चलेगी। ऑडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और विष्वा के नेता एवं बीजत अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सहातय के अवसर पर ऑडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दीं और मां दुर्गा के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की।

&lt;/



**उत्तराखण्डः धामी ने जनप्रतिनिधियों से जीएसटी पर जागरूकता बढ़ाने को कहा**

देहरादून, फोकस न्यूज, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की नई दरों और रखदाता अभियान पर जनप्रतिनिधियों से जनजागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। वीडियो कॉफ्रेस के जरिये प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दरों का लाभ आम जनता और व्यापारिक समुदाय तक तेजी से पहुंचाने के लिए प्रदेश में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से 22 से 28 से 30 सितंबर तक अपने-अपने देश के जागरूकता कार्यक्रमों का सचालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रभारी मंत्री अपने जिलों में तथा विधायक अपनी विधायकमाओं में अभियान का नेतृत्व करेंगे। देश और राज्य की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में प्रयोग नागरिक के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए धामी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि स्वयं इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं और इसे जन अभियान का स्वरूप दें।

मुख्यमंत्री की नए दरों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नेरेंद्र मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतामानी को आभार दिया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की अंधव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि नवी जीएसटी दरों से उत्तराखण्ड के अंडेल ब्रांड "हाउस ऑफ हिमालयाज" और जीआई टैग प्राप्त 27 उत्पाद, एक जनपद दो उत्पाद योजना तथा अन्य स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की परिकल्पना को साकार करने में सहयोग मिलेगा।

### न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मोटर दुर्घटना दावों के लिए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का डैशबोर्ड लॉन्च किया

नयी दिल्ली, (भाषा) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने रविवार को मध्यप्रदेश की न्यायपालिका के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया, जो मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे से संबंधित सभी सुचनाएं प्रदान करने वाले मंच के रूप में काम करेगा। एक बयान के मुताबिक, "शीर्ष अदालत के 22 अप्रैल 2025 के आदेश के अनुपाधिन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 'मोटर दुर्घटना दावा न्यायिकरण के लिए दावों का प्रतिपूर्ति और जमा प्रणाली को शाफिर डैशबोर्ड बनाएंगे' विकास किया है।" उच्चमन्त्र न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि "ई-कोर्ट परियोजना के केंद्रीय परियोजना समर्पयक, या उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार (कंप्यूटर/आईटी), संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाएंगे।"

### टिकाऊ स्टार्टअप के लिए उद्योग संपर्क, निजी क्षेत्र की भागीदारी अनिवार्य: जितेंद्र सिंह

जम्मू, फोकस न्यूज, भारत के टिकाऊ स्टार्टअप और आर्थिक वृद्धि के लिए उद्योग संपर्क और निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को यह बात कही। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने यहां 'लौड इम्पैक्ट कॉन्वेल' को संवाद करते हुए कहा कि सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के एक सक्षम परिस्थितिकी तरफ बनाया है।

उन्होंने कहा कि स्टार्टअप अभियान के एक आकर्षक और स्थायी स्रोत के रूप में उभरे हैं। उन्होंने लगभग 60,000 स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं, जो सफल कृषि उद्यमी बन गई हैं।



"मंत्री ने प्रासादिक क्षेत्रों में उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग का आवधान किया। उन्होंने आने वाले वर्षों में प्रासादिक विषयों पर शोध की वकालत करते हुए कहा कि अगली क्रांति जैव-संचालित होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया आने वाले समय में भारत से नेतृत्व की भूमिका निभाने की उम्मीद कर रही है।

### हिमाचल सरकार बिजली बोर्ड में 2600 युवाओं की भर्ती करेगी

शिमला, (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड में फील्ड कर्मचारियों की कमी को दूर करने और बिजली सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 2,600 से अधिक युवाओं की नियुक्ति को मंजूरी दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 1,602 चयनित अधिकारियों को 'बिजली उपभोक्ता मित्र' तथा 1,000 को 'टी-मेंट्स' के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा, "वर्दमान में टी-मेंट्स के 4,009 स्टीरीकृत पद पद हैं जिनमें से 3,049 रिक्त हैं, जिससे संचालन और सेवाओं की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सरकारी प्रवक्ता के लिए 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्र की नियुक्ति एक अधिकृत मित्र और 1,000 टी-मेंट्स की भर्ती करना का नियन्त्रण किया है।" उन्होंने आने वाली वर्षों में से जीएगी, जिन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण के लिए नियमित आयु सीमा 18 से 20 वर्ष है। उन्होंने कहा कि फील्ड कर्मचारी एचपीएसईबीएल की रीढ़ है, जो बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है और आपदाओं के दौरान अतिग्रस्त ढांचे की रूपमत कर बिजली बहाल करने में अहम भूमिका निभाता है।

### तमिलनाडु भाजपा प्रमुख ने पनीरसेल्वम व दिनाकरण को राजग में वापस लाने पर कोई प्रतिबद्धता नहीं जारी



सेलम, (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नैनार नारेंद्रन ने रविवार को यहां अन्नाद्रमुक महासचिव ई. के. पलानीस्वामी से मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पलानीसेल्वम और एसएमके को राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन (राजा) में वापस लाने की संभावना पर कोई प्रतिबद्धता जाताने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष ने अलै इंडिया अन्ना द्रव्यमाला मुनेवर करायम (अन्नाद्रमुक) प्रमुख के साथ बैठक को 'शिवाचार भेट' बताया और उनके साथ राजीनीति पर चर्चा करने से इनकार किया। पत्रकारों ने नारेंद्रन से पूछा कि पट्टानी मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक नेता एस. रामदास का गुट कथित तीर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मार्ग रहा है और आरोप लग रहे हैं कि भाजपा अन्य दलों के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है। इस पर नारेंद्रन ने कहा, "भाजपा किसी भी राजनीतिक दल के अंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।"

### धरती का सच और हमारा कल



इंसान का इतिहास दो तस्वीरों में बँटा है। पहली तस्वीर—जिसमें इंसान खेतों में करते हैं। यह कहानी सिर्फ उस गाँव की नहीं—यह हर जगह हो रही है। अनाज उत्तरा है, पुल बनाता है, नदियों पर बांध खड़ा करता है, बीमार का इलाज करता है, और बच्चों को पढ़ाता है। दूसरी तस्वीर—जिसमें वही इंसान धरती के टुकड़े करता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हथियार बनाता है, और अपने छोटे स्वार्थों के लिए लाता है। इसमें वही इंसान धरती के टुकड़े करता है, जो जाति, धर्म, भाषा, प्रांत और देश। अब यह खाँचे दीवारों में बदल गए हैं। और उन दीवारों को गिराने की जगह हम उत्तर और ऊँचा करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक छोटा खड़ा पर चर्चा करते हैं। अब यह खाँचे दीवारों में बदल गए हैं। और उन दीवारों को गिराने की जगह हम उत्तर और ऊँचा करते हैं।

पहले लोग हँसकर बात टाल देते, लेकिन बीज बो दिया गया था। महीनों में शक की बैठक फैल गई। त्योहारों की मिटाई का आदान-प्रदान बंद हो गया। एक दूसरे के पर्व त्योहार पर आना जाना खूबी रही। हमलोग गाय की पूजा करते हैं, जो लोग उसे काटकर खाते हैं। इसी तरह की बहुत सारी एकदूसरे धर्म वाले से नफरत की बातें करते हैं। इतिहास गवाह है—जग में जीत कोई नहीं पाता। हार हार किसी की हाती है।

शांति, में, हम मिलकर बैठते हैं, विवाद

सुलझता है, और ऐसा भविष्य बनाते हैं जिसने

पढ़ा हुई।

शांति में, हम मिलकर बैठते हैं, विवाद

सुलझता है, और ऐसा भविष्य बनाते हैं जिसने

पढ़ा हुई।

शांति में, हम मिलकर बैठते हैं, विवाद

सुलझता है, और ऐसा भविष्य बनाते हैं जिसने

पढ़ा हुई।

शांति में, हम मिलकर बैठते हैं, विवाद

सुलझता है, और ऐसा भविष्य बनाते हैं जिसने

पढ़ा हुई।

शांति में, हम मिलकर बैठते हैं, विवाद

सुलझता है, और ऐसा भविष्य बनाते हैं जिसने

पढ़ा हुई।

शांति में, हम मिलकर बैठते हैं, विवाद

सुलझता है, और ऐसा भविष्य बनाते हैं जिसने

पढ़ा हुई।

शांति में, हम मिलकर बैठते हैं, विवाद

सुलझता है, और ऐसा भविष्य बनाते हैं जिसने



## अमूल ने धी, मक्खन, आइसक्रीम सहित 700 से ज्यादा उत्पाद पैक की कीमत घटाई

नयी दिल्ली, (भाषा) अमूल ब्रॉड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाली जीसीएमएफ ने शनिवार को धी, मक्खन, आइसक्रीम, बैकरी और फ्रौजन सैक्स सहित 700 से अधिक उत्पाद पैक की खुदरा कीमतों में कमी की। कंपनी ने जीएसटी दर में कटौती का लाभ उपयोगिताओं तक पहुंचाने का फैसला किया है। नयी कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। गुजरात सहकारी दुध प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के एक सम्मेलन को यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार अदालतों द्वारा ठोस फैसले दिए जाने के बावजूद सरकारी अधिकारी दायर कर देते हैं। उन्होंने सकेत दिया कि कभी—कभी अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए अदालत या कैट के आदेशों को चुनौती देने के लिए अपील दायर करते हैं, क्योंकि फैसलों में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाए गए होते हैं। मेघवाल ने कहा कि उन्हें नियमित रूप से ऐसी फैलें मिलती रहती हैं, जिनमें केंद्रीय विभाग द्वारा अदालती आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की योजना बना रही होते हैं। उन्होंने कहा कि सीएटी (कैट) को ई-फाइलिंग और डिजिटल सुनवाई जैसी नवीनतम काटोंकों का उपयोग करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूगोल न्याय प्रदान करने में साथीय व्यापारों को बचाया होगा, ताकि यह उच्च न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम करने में व्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की।

## विजयन 'नकली भक्त' हैं, चुनाव के लिए किया

### जा रहा अय्या संगम का आयोजन: सतीशन

कोचिं, (भाषा) केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने शनिवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को "नकली भक्त" कराया देते हुए आरोप लगाया कि "आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर" अय्या संगम का आयोजन किया जा रहा है। ब्रावोनकोर देवस्वम बोर्ड की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अय्या संगम का आयोजन किया जा रहा है। कोठामंगलम में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सतीशन ने पत्रकारों के साथ बातचीत में दावा किया, "मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उद्घाटन के बाद एक नकली भक्त की तरह बात की। यह भक्ति, जो कभी उनपर किट नहीं बैठी, आगमी चुनाव को ध्यान में रखकर रवीं गई एक चाल बोला है।

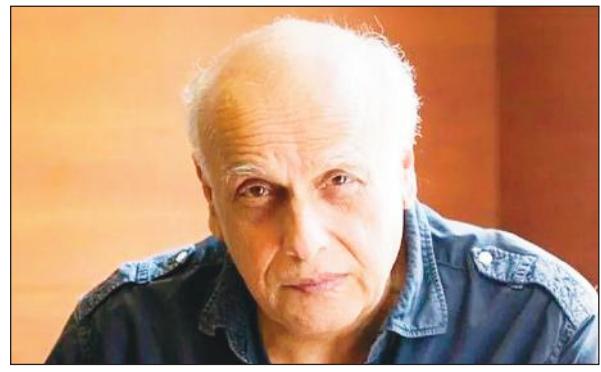
वह पुलिस की मदद से सरकारीमाल में हुए अत्याचारों को छिपा रखे हैं, अपने कार्यकाल के दौरान पर्पराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। सतीशन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में महिलाओं के प्रवेश और भक्तों पर दर्ज मामलों को वापस लेने से जुड़े हलफनामे को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा, "यह राजनीति का एक अलग रूप है जिसपर धर्म का रंग चढ़ाया गया है। हमारे लिए धर्म और भक्ति निजी मामले हैं।" विपक्ष के नेता ने सबरीमला से संबोधित मुद्दों से निपटने के सरकार के तरीके की आलाचना की और कहा कि संयुक्त लोकतात्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की पिछली सरकार ने मंदिर के विकास के लिए 112 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण किया था, लेकिन अब तक वहां कोई काम नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में सबरीमला में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है।

## सीजीएल परीक्षा के करीब 10,000 अभ्यर्थियों से नये पोर्टल पर प्रतिक्रिया मिली : एसएससी

नयी दिल्ली, (भाषा) कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने शनिवार को कहा कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल) 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से नये "फ्रैंडेक" पोर्टल पर उत्सुहजनक प्रतिक्रिया मिली हैं और इसके लॉन्च होने के एक सप्ताह के भीतर लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 2,000 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के दौरान कथित तकनीकी व्यवहार की सूचना दी। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, आयोग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रत्येक मामले का सांवधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा, "जहां व्यवहार वास्तविक पाया जाएगा, प्रभावित अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। पर्याप्तरीका वर्षान्तर से अपरिवर्तनीय वर्षान्तर के बीच खासकर ग्रामीणों तक यह खबर फैल गयी थी कि कोई सत निकला है जो दान में भूमिहीनों के लिए जमीन मांगता है और कहता है कि हमा, पानी और आसमान की तरह जमीन मी इंश्वर की बनाई हुई है जो सबके लिए है। अप मुझे अपना बेटा मानकर अपनी जमीन का छठा विस्ता दे दीजिए।" एसएससी ने रेखांकित किया कि वह परीक्षाओं के संचालन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक, देश भर में 7.16 लाख अभ्यर्थी सफलतापूर्वक परीक्षा दे चुके हैं। अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की कि 19 सितंबर तक, किसी भी पाती की परीक्षा रद्द या पुनर्निर्धारित नहीं की गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि पूरी प्रक्रिया सुचारू रही।



'अर्थ' से पूर्व मेरा करियर खत्म मान लिया गया था, महेश भट्ट ने साझा की शुरुआती विफलताओं की कहानी'



मुंबई, (भाषा) फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने कहा है कि वह आज भी खुद को एक 'लड़खड़ाता और ठोकर खाता इंसान' मानते हैं, जिन्होंने जब फिल्म उद्योग में कदम रखा तब लगातार असफलताएं डॉलीं। महेश भट्ट ने दिवंगत राज खोसला के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। उन्होंने 1974 में 'मंजिलें और भी हैं' से निर्देशन में कदम रखा। हालांकि कबीर बेदी रखा था। नारायण अभिनीत यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इसके बाद उन्होंने विवाहसंघात, 'नया दोर, 'लहू के दो रंग' जैसी फिल्में बनाईं, जो दर्शकों पर कुछ खास असर नहीं छोड़ पाईं। महेश भट्ट को तब सफलता मिली जब उन्होंने आत्मकथा पर आंशिक रूप से आधारित फिल्में—'अर्थ', 'जन्म', 'जार्ज' बनायीं। उन्होंने कहा, '20 की उम्र के बाद का एक दशक मेरे लिए बहुत खराब रहा। मेरी तीन-चार फिल्में लेकिन लगातार नाकाम्याब रहीं। 'अर्थ' फिल्म रिलीज होने पर वहले समझ लिया गया कि मेरा करियर खत्म हो गया है।' उन्होंने कहा, 'मैं बस एक सधार्हरत, लड़खड़ाता और हक्काता हुआ इंसान हूं। कुछ फिल्में मैंने बनाईं जो अच्छी निकली लेकिन वे सेट पर मौजूद सामूहिक ऊर्जा और मेरे साथियों के योगदान के बजाए से थीं।' निर्देशक निर्माता नानामाई भट्ट के बेटे महेश भट्ट (76) ने बताया कि उन्होंने कभी खुद को फिल्मकार नहीं माना क्योंकि वह केवल रोजगार की तलाश में इस उद्योग में आए थे। उन्होंने कहा, '15 साल की उम्र में मेरी मां ने मुझसे कहा, 'तुम्हारे पापा मुश्किल में है, हमें पैसे की जरूरत है। तुम्हारी बहन 'एयरोस्पेस इंजीनियर' के रूप में काम करने लगी है। तुम यहां बैठे हो और मेरे सामने खा रहे हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता।' उन्होंने याद करते हुए कहा, 'मैंने खाना बही रख दिया, हाथ पांचे और अपने दोस्त असपार अली के पास जाकर चिल्लाया: 'मूँझे कोई काम दिला।' मैंने पर्वत स्थित किलिक निकलन में टर्नर और फिर के रूप में काम शुरू किया। मेरी पहली हपते की तनबाह 58 रुपये थीं। मैंने वो पैसे अपनी मां को दिए। मैंने बस खाने के लिए काम किया।' महेश भट्ट ने बताया कि वह अच्छे विद्यार्थी नहीं थे और कॉलेज छोड़ दिया था लेकिन उन्हें कहनियां सुनाकर जीवन में आगे बढ़ने की कला आती थी। उन्होंने कहा, 'मेरा बचपन शायद सामाज्य धरों के मानकों के अनुसार कुछ हड तक त्रस्त था। मैंने खुद को संभालने के लिए बेसब्री का सहारा लिया। मेरी कहानी कहने की कला वही से शुरू हुई लेकिन जब मैंने शुरुआत की, तब भी मैं लड़खड़ाता रहा, गिरता रहा।' भट्ट ने कहा, 'अगर आप असफलता से डरते हैं तो इस उद्योग में मत आइए। यहां असफलता हमेशा साथ रहती है, सफलता एक संयोग मात्र है। अगर आप में सार्वजनिक रूप से असफल होने, आलोचना सहने का साहस है, तभी आइए, बरना उत्तिर और यहा से निकल जाइए।' जब उनसे पूछा गया कि उनकी निजी जिजिदी और फिल्में जैसे 'अर्थ', 'जन्म' और 'वो लाल्हे' अक्सर एक-दूसरे में कैसे जुड़ी रहीं तो भट्ट ने कहा कि उनके लिए यह सहज था क्योंकि सिनेमा ही उनकी अभिव्यक्ति का मायम था।

फिल्म 'होमबाउंड' को ऑस्कर के लिए चुने जाने पर करीना कपूर, अनिल कपूर और अन्य ने दी बधाई

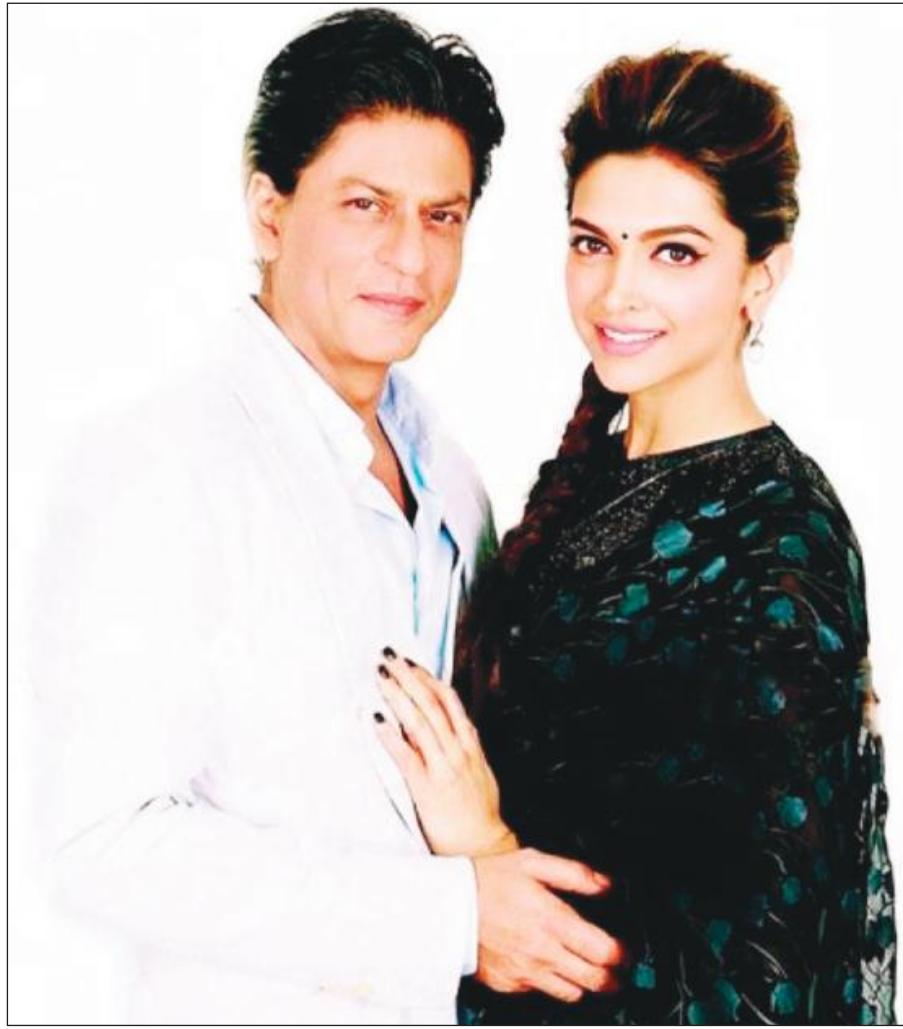


नयी दिल्ली, फॉकस न्यूज, बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे, करीना कपूर खान और अनिल कपूर सहित कई मशहूर हस्तियों ने नीरज घायवान निर्देशित फिल्म 'होमबाउंड' के भारत की ओर आधिकारिक तौर पर ऑस्कर के लिए चुने जाने पर फिल्म की टीम को शुभकामनाएं दीं और इसे 'गर्व का क्षण' बताया। करण जौहर और अदार पूरावाला द्वारा निर्मित इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेटवा और जान्हवी कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई हैं। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले अकादमी पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फौर्क श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में फिल्म 'होमबाउंड' को शुक्रवार को चुना गया। अनन्या ने सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर शुक्रवार को फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए घायवान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'वाह!! यह अविवासनीय है। पूरी टीम को बधाई।' सिनेमाघरों में इस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली फिल्म को देखने का बेसब्री से इंतजार है। आप जो भी बनाते हैं वह बहुत अच्छा होता है। आप के लिए बहुत खुश हूं।' करीना ने कहा कि वह फिल्म देखने के लिए उत्साहित है। करण जौहर को बधाई। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।' अनिल ने कपूर ने कहा कि उन्हें इतना गर्व है कि उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने कहा, 'इतना गर्व है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।' फिल्म 'होमबाउंड' ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। पूरी टीम और ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेटवा को बधाई। आपका सफर, आपकी प्रतिभा और पर्वं पर आपकी इमानदारी इस पल को बार्कइ खास बनाती है।' सारा अली खान ने कहा, 'बधाई हो।' यह बहुत बड़ी बात है!! फिल्म 'होमबाउंड' की पूरी टीम के लिए बहुत खुश हूं।' शानाया कपूर ने कहा, 'पूरी टीम को बधाई! 26 तारीख का बेसब्री से इंतजार है।' यह गर्व और अविवासनीय क्षण है।'

शाहिद कपूर ने फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए कहा, 'बधाई हो।' फिल्म को कान फिल्म महोत्सव में अन स्टैन रिगार्ड श्रेणी में चुना गया था और हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी यह प्रदर्शित की गई थी। 'होमबाउंड' को चयन समिति के अध्यक्ष एन. चंद्रा द्वारा ऑस्कर में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। यह फिल्म प्रतिकार बशारत पीर के 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के लेख 'टेकिंग अमृत होन' से प्रेरित है, जिसका शुर्खी भी (ए फ्रॉन्टशिप, ए पैनडेमिक एंड ए डेथ बिसाइड द हाईवर) है। यह उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के दो बचपन के दोस्तों की कहानी है, जिनमें से एक मुसलमान और दूसरे दलित है, जो पुलिस की नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं, जिनमें से उन्हें वह सम्मान दिलाने का बाद करती है, जिससे वे लंबे समय से वंचित हैं।

'कलिक 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर होने के बाद दीपिका ने शाहरुख के साथ शुरू की 'किंग' की शूटिंग



नयी दिल्ली, बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनेता शाहरुख खान के साथ अपनी आगामी फिल्म 'किंग' की शूटिंग शुरू करने पर सोशल मीडिया पर दिल को छू जाने वाली एक पोस्ट लिली। दीपिका और शाहरुख की यह छठी फिल्म होगी। इससे पहले उन्होंने 'ओम शति ओम' (2007), 'चैन्स एक्सप्रेस' (2013), 'हैप्पी न्यू इंडर' (2014), 'पठान' (2023) और 'जवान' (2023) में साथ किया था। दीपिका और अई तेलगु लॉकबस्टर 'कलिक 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर हो गई थी। अभिनेत्री ने एक मुख्यालय सीख देने के लिए शाहरुख का आभार जताया और कहा कि उन्होंने अपने हाफे से में इस बात को लागू किया। अभिनेत्री ने लिखा, 'उन्होंने (शाहरुख) ने लगभग 18 साल पहले ओम शांति ओम की शूटिंग के दौरान मुझे जो पहली सीख दी थी वह फिल्म बनाने का अनुभव था। उन्होंने कहा था कि आप जिन लोगों के साथ मिलकर फिल्म बनाते हैं, वे फिल्म की सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।' दीपिका (39) ने शाहरुख का हाथ पकड़े हुए एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की और लिखा, 'मैंने तब से गाट बांध ली और अपने हारे फैसले में इस सीख को लागू किया है। और शायद यही वजह है कि हम साथ में अपनी छठी फिल्म बना रहे हैं।' बताया जा रहा है कि इस नपी फिल्म 'किंग' में शाहरुख की बेटी सुरुदाना खान भी होगी। इससे पहले, बहस्पतिवार को 'कलिक 2898 एडी' के निर्माताओं ने घोषणा की थी कि दीपिका फिल्म के सीक्वल में नहीं होंगी। नग अविन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण करने वाले वैजयंती मूर्खी लॉकडायों ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर यह खबर साझा की थी। पोस्ट में कहा गया था, 'आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण... 'कलिक 2898 एडी' के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है।' पहली फिल्म बनाने की लंबी यात्रा के बावजूद हम साथेदारी कायम नहीं रख पाए।' और 'कलिक 2898 एडी' जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं ज्यादा की हड्डी रहा। हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।' फिल्म जून 2024 में प्रदर्शित हुई थी और वैयिक स्तर बॉक्स ऑफिस पर इसने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।

**What does Delhi mean to you?**  
Express it with your creativity!

**Participate in the LOGO DESIGN COMPETITION for Government of NCT of Delhi**

& showcase the city's rich past & vibrant culture

Visit: [Mygov.in](http://Mygov.in)

**my**  
**GOV**  
मेरी सरकार

**रूस के काल्मिकिया में किया जाएगा**  
**भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन**

लखनऊ, (भाषा) उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु स्थित पिपरहवा में रखे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का रूस के काल्मिकिया में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इन अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए ले जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यहां रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय आगामी 24 सितंबर से एक अवटूबर तक रूस के काल्मिकिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य पवित्र अवशेषों को रूस ले जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। मौर्य प्रतिनिधिमंडल के साथ 23 सितंबर को भारतीय वायुसेना के विमान से रूस रवाना होंगे। प्रतिनिधिमंडल अपने साथ भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा (कपिलवस्तु) अवशेषों को ले जाएगा। बयान के अनुसार, काल्मिकिया ऐसा क्षेत्र है जहां बौद्ध धर्मावलम्बियों की खासी आबादी है और वहां बौद्ध धर्म के वेल मजहब ही नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। मौर्य ने बताया कि कपिलवस्तु अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा भारत की 'सॉफ्टपावर' और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रभावी माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा, "इससे पहले थाईलैंड और वियतनाम में भगवान बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित की जा चुकी है। थाईलैंड और वियतनाम की सफलता ने वैश्वक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ायी है।" मौर्य ने बताया कि रूस में होने वाली प्रदर्शनी इस गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाएगी और भारत की सांस्कृतिक छवि को और निखारेगी जिससे द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ सांस्कृतिक व राजनीतिक रिश्तों में और गहराई आएगी।

होटल में 7,500 रुपये तक किराये वाले कमरे सोमवार से 525 रुपये तक सस्ते होंगे। नई दिल्ली, (भाषा) नई जीएसटी दरें लाग होने के साथ ही होटल में 7,500 रुपये या उससे कम किराये वाले कमरे सोमवार से 525 रुपये तक सस्ते होंगे।

**नया होल्ला, (भाषा)** नई जाएसटा दर लागू हान के साथ हा होटल म 7,500 रुपय या उसस कम कराय वाल कमर सामवार से 525 रुपय तक सस्त हा जाएग। आतिथ्य क्षेत्र के दिग्गजों ने कहा कि होटल उद्योग के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने से बुद्धि को समर्थन मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और होटल देश भर में मेहमानों को बेहतर सेवाएं दे सकेंगे। इस समय 7,500 रुपय तक के दैनिक किराये वाले होटल के कमरों पर आईटीसी के साथ 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, इस कटौती से कमरे का किराया सात प्रतिशत सस्ता होगा। इसी प्रकार यात्रियों को भोजन पर जीएसटी का लाभ भी मिलेगा। रेडिसन होटल समूह के दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) निखिल शर्मा ने पीटीआई-भाषा को बताया कि सरलीकृत कर संरचना होटल संचालकों और यात्रियों के लिए स्पष्टता लाएगी। रमाडा जैसे ब्रांड के मालिक, विन्धम होटल्स एंड रिझॉर्ट्स के यूरेशिया बाजार के प्रबंध निदेशक राहुल मैकरियस ने कहा कि भारत का यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र मजबूती से बढ़ रहा है और जीएसटी सुधार बिल्कुल सही समय पर आया है।

**विपक्ष को जेन जी का एक और झटका!, डूसू के बाद अब एबीवीपी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में लहराया जीत का परचम हैदराबाद। विपक्ष को जेन जी लम्दे-८ ने एक और झटका दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (डूसू) में अध्यक्ष समेत 3 पदों पर जीत दर्ज करने के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में अपना परचम लहराया है। एबीवीपी ने सेवा लाल विद्यार्थी दल (एसएलवीडी) के साथ मिलकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्रसंघ का चुनाव लड़ा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्रसंघ में एबीवीपी—एसएलवीडी गठबंधन के शिव पालेपु ने अध्यक्ष पद जीत लिया। वर्हे देवेंद्र ने उपाध्यक्ष पद जीता। महासचिव पद पर श्रुति प्रिया और संयुक्त सचिव पद पर सौरभ शुक्ला की जीत हुई। एबीवीपी—एलएलवीडी गठबंधन की वीनस सांस्कृतिक सचिव चुनी गई। वहीं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के खेल सचिव पद पर गठबंधन के ज्वाला ने कब्जा जमाया। इससे पहले एबीवीपी ने बीते दिनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ में अध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के अहम पद जीते हैं। एबीपीवी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में कांग्रेस के एनएसयूआई को जोरदार पटका दी थी। एनएसयूआई सिर्फ उपाध्यक्ष का पद हासिल कर सकी थी। इससे पहले एबीवीपी ने 2024 में पटना यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी समेत कई यूनिवर्सिटीज के छात्रसंघ चुनाव में परचम लहराया था। एबीवीपी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है। साथ ही यूनिवर्सिटीज के प्रशासन से बात कर छात्रों को होने वाला तमाम दिक्कतों को दूर भी कराया है। इसके साथ ही बीजेपी और एबीवीवी नेताओं की रणनीति ने भी छात्रसंघों में उसकी पैठ कराने में काफी मदद की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के बाद हैदराबाद छात्रसंघ में एबीवीपी की जीत से विपक्ष को जोरदार झटका लगन तय है। क्योंकि विपक्ष हाल के दिनों में लगातार जेन जी और युवा वर्ग का आह्वान करता रहा है कि वो बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ उठ खड़े हों। वहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हालांकि विपक्ष के आह्वान के खिलाफ अपना रुख जाहिर कर दिया है। एबीवीपी की दिल्ली और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जीत से बीजेपी को भी युवाओं में से ज्यादातर के अपने पक्ष में होने का पता चला है। जाहिर है इससे बीजेपी का मनोबल भी बढ़ेगा।**

# काजीरंगा विश्वविद्यालय में नगालैंड के छात्र सुरक्षितः मंत्री

**कोहिमा, (भाषा)** नगालैंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री तेम्जेन इम्ना अलोंग ने रविवार को कहा कि असम के जोरहाट स्थित काजीरंगा विश्वविद्यालय में पर रहे राज्य के छात्र सुरक्षित हैं। मंत्री का यह बयान दिवंगत असमिया गायक जुबिन गर्ग के बारे में एक नगा छात्र द्वारा की गई टिप्पणी से उत्पन्न हुए तनाव के बाबा आया है। अलोंग ने संवाददाताओं को बताया कि यह घटनाक्रम शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे शुरू हुआ और देर रात दो बजे तक जारी रहा। यह तनाव बी.टेक के एक छात्र की टिप्पणी से स्थानीय भावनाएं आहत होने के बाद पैदा हुआ उह्होंने कहा कि छात्र को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, जबकि विश्वविद्यालय में नामांकित 300-400 से अधिक नगा छात्र सुरक्षित हैं। इस बीच, काजीरंगा विश्वविद्यालय तनाव के विवाद के केंद्र में रहे नगा छात्र ने रविवार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। अपने बयान में, छात्र लिसरी एस. संगतम ने कहा, “मैं अपने कार्यों और आचरण के लिए क्षमाप्रार्थी हूं जिससे असम के नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंची। दिवंगत प्रिय गायक जुबिन गर्ग का अनादर करने का मेरा कोः इरादा नहीं था। हालांकि, मैं असम के सभी समुदायों से क्षमा चाहता हूं।” छात्र ने कहा, “दिवंगत जुबिन गर्ग दा और उनके प्रशंसकों से क्षमा याचना करते हुए भविष्य में ऐसी हरकतें दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी।” संगतम ने कहा कि वह असम के लोगों और उन सभी समुदायों से क्षमा मांगते हैं जिन्हें ठेस पहुंची है। मंत्री ने त्वरित हस्तक्षेप और नगालैंड अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए असम सरकार पुलिस और काजीरंगा विश्वविद्यालय प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया। मंत्री ने कहा, “स्थिति अब सामान्य है। भीड़ के गुरुसे में बेकाबू हो जाने के अलावा कोः बड़ी चोट या अप्रिय घटना नहीं हुई।” अलोंग ने माना कि गर्ग की मौत पर व्यापक शोक को देखते हुए छात्र की टिप्पणी अनुचित थी, और उह्होंने असम तथा अपने देश में नगा लोगों से सोशल मीडिया पर संयम बरतने की अपील की। उह्होंने कहा, “जब हमारा अपना कोई लड़का ऐसी गलती करता है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, तो सबसे पहले तो गुरुसे में या युशी में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम भी समझते हैं, दिवंगत जुबिन गर्ग जैसम के लोगों के दिल के बहुत करीब हैं और विना संवेदनशीलता के बोले गाये ऐसे विचार गलत हैं।” छात्र या वहां पढ़ रहे अन्य नगा छात्रों के खिलाफ संभावित अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में मंत्री ने मामले को संवेदनशील बताया, लेकिन उम्मीद जाताई कि काजीरंगा विश्वविद्यालय कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा।

# समुद्री खाद्य प्रदर्शनी में 15 से अधिक देशों की कृपनियां भाग लेंगी

नयी दिल्ली, (भाषा) अमेरिका, यूरोपीय संघ, वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, बेल्जियम, जापान और चीन जैसे प्रमुख बाजारों सहित 15 से अधिक देशों के प्रतिभागी बृहस्पतिवार से शुरू होने वाली समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 'इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो' में भाग लेंगे। एक बयान में कहा गया है कि वैश्विक आयोजन का 24वां संस्करण 'वर्ल्ड फूड इंडिया-2025' का हिस्सा होगा, जो भारत सरकार का प्रमुख वैश्विक खाद्य नवाचार कार्यक्रम है। एशिया का प्रमुख समुद्री खाद्य व्यापार मेला, इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो (आईआईएसएस-2025), 25 र 28 सितंबर तक नयी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) द्वारा किया जा रहा है। बयान के अनुसार, इसमें 260 से अधिक स्टॉल, तकनीकी सत्र और गोलमेज परिचर्चाएं शामिल होंगी। इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, वियतनाम, यूएई, जर्मनी, बेल्जियम, जापान, चीन सहित 15 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डिवेलपमेंट थर्डिंस्टी (एमपीईडी) द्वारा आयोजित एक रिवर्स बायर-सेलर मीट भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे जोड़कर व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगी। सीईएआई व अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा, 'हम अपनी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और यह श भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करने तथा नए बाजारों में विस्तार करने में मदद करेगा।' सीईएआई के महासचिव के.एन. राघवन ने कहा, 'हमारा ध्येय वाक्य 'सर्वेनेबली हार्वेस्टेड, ह्यूमैनली सोसर्ड' हमारे नैतिक और जिम्मेदार मछली पालन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह मंच कौशल विकास, स्थायित्व और नवाचार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेगा।'

# महलों का शहर मैसूर दशहरा उत्सव के लिए तैयार

मुसरु, (भाषा) वष का वह समय एवं बार फिर आ गया है, जब यह ऐतिहासिक नगरी सालाना दशहर उत्सव की तैयारियों में रंग-बिरंगे रोशनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों रंग सज उठती है। वर्ष 1610 में शुरू हुए नवरात्रि पर्व की परंपरा को आगे बढ़ा हुए इस बार भी शहर में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की शून्खल आरंभ हो गई है, जो न सिर्फ स्थानीय निवासियों बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र बनी हुई है। 'नाडा हब्बा' (राजस्थान उत्सव) के रूप में मनाए जाने वाले साथ-साथ शाही वैभव की झलक उड़द्घाटन को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ है। चंद्र विजय से शुरू होकर विजयादशमी यानी वह सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मनाया जाता था। अब यह त्योहार को सुबह 10:10 से 10:40 के शुभ व्रद्धी चंद्र देवी चामुडेश्वरी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री सिहरमैया, उनके कई मंत्री कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस पर सरकार द्वारा मुश्ताक को समारोह के का कहना है कि इस पर्व की शुरुआत में मुश्ताक को आमंत्रित करना धार्मिक जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर जताई थी। हालांकि, मुश्ताक का कहना किया गया। अधिकारियों ने बताया कि



केरल के मुख्यमंत्री ने न्यू जर्सी के गवर्नर  
मर्फी को निवेश के लिए आमंत्रित किया



**कोच्चि, फोकस न्यूज़, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को न्यू जर्सी के गवर्नर फिलिप डी मर्फी और अमेरिका के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें केरल में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। एक सरकारी बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान विजयन ने राज्य के मजबूत बुनियादी ढांचे, उच्च साक्षरता और व्यवसायों के लिए सरल प्रक्रियाओं के साथ ही निवेशक-अनुकूल वातावरण के बारे में बताया। विजयन ने कहा कि केरल और न्यू जर्सी विकास के क्षेत्र में कई समानताएं साझा करते हैं और इस बात पर जोर दिया कि निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। बयान में आगे कहा गया, 'केरल में उद्योगों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। पर्यटन, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों ने राज्य को निवेशकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना दिया है। चार हवाई अड्डे, 18 बंदरगाह और सरल औद्योगिक प्रक्रियाएं केरल को आकर्षक बनाती हैं।' शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नत करके केरल को ज्ञान आधारित समाज बनाना है।**

## राजस्थान में 22 सितम्बर से मनाया जाएगा 'जीएसटी बचत उत्सव'

जयपुर, राजस्थान में 22 सितम्बर से 'जीएसटी बचत उत्सव' मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में माल व सेवा कर (जीएसटी) दरों में संशोधन से गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योगपतियों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देशवासियों को त्योहारों पर जीएसटी दरों में कमी की अनूठी सौगात दी गई है। इसका व्यापक लाभ सुनिश्चित करने के लिए जन-जागरूकता आवश्यक है। शर्मा जीएसटी दरों के संबंध में मंत्रियों और विधायकों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी सुधार एवं दर युक्तिकरण जन-जागरूकता कार्यक्रम 'जीएसटी बचत उत्सव' शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ ही व्यवसायी वर्ग को प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि इस कदम से दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं सस्ती होंगी और आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। शर्मा ने कहा कि कर कम होने से वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, व्यापारी लाभान्वित होंगे तथा उद्योगों को सरल कर संरचना का लाभ मिलेगा।

अहिल्या बाई और राजा भोज की नगरी धार से गूंजा राष्ट्रवाद और विकास का संदेश



**पवन वर्मा**  
विश्वकर्मा जयंती के दिन मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक नगर धार की धरती एक बार फिर इतिहास का साक्षी बनी। इस दिन प्रधानमंत्री ने भौतिक संरचना के साथ-साथ विज्ञान तथा सांस्कृतिक समावेशी, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। मोदी के अनुसार, यदि इन चार वर्गों को सशक्त किया जाए तो भारत दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होएगा।

नरंद्र मादो न यहां एक विशाल जनसभा का संबोधित करते हुए न सिर्फ भारत के समृद्धशाली, ऐतिहासिक इतिहास की याद दिलाई, बल्कि आधुनिक भारत के भविष्य की भी स्पष्ट झुपरेखा प्रस्तुत की। यह भाषण एक ओर जहां राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत था, वहीं दूसरी ओर आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास की भी मजबूत पैरवी करता नजर आया। प्रधानमंत्री के इस संबोधन ने धार की ऐतिहासिकता को करने में सक्षम हांगा।

**'अहिल्या की धरती से स्वस्थ नारी और सशक्त राष्ट्र का नारा'**: कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नारी सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि धार से जो कार्यक्रम आरंभ हो रहा है, वह केवल इस जिले या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की माताओं और बहनों के लिए समर्पित है। यह कार्यक्रम केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं है, बल्कि यह सशक्त

परिवार और सशक्त समाज के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। इस योजना को विशेष रूप से जनजातीय समाज की महिलाओं से जोड़ने की चेष्टिका की जा रही है। ये भव तक सामाजिक

शुरुआत धार को महिमा का बखान करते हुए की। धार, जो मध्यकालीन भारत में मालवा की राजधानी रही है और महाराजा भोज जैसे महान राजा की कर्मभूमि रही है, उसे उन्होंने पराक्रम और प्रेरणा की धरती बताया। महाराजा भोज का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका को काशश को जा रही है, जो अब तक मुख्यधारा की योजनाओं से अपेक्षाकृत दूर रही है। ‘औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआतः टेक्सटाइल पार्क’ः विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रधानमंत्री ने देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी। यह केवल

स्थैर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए प्रेरित करता है और मानवता की सेवा का संकल्प देता है। ‘आतंक पर करारा प्रहार और आत्मविश्वास की हुँकार’: प्रधानमंत्री मोदी का भाषण राष्ट्र सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नीति के संकल्प से भी परिपूर्ण था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमारे देश की बहनों-बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, तब भारत ने “ऑपरेशन सिंदूर” के माध्यम से उनका करारा जवाब दिया। यह नामकरण ही प्रतीकात्मक रूप से देश की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब किसी की परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं रहा। यह घर में घुसकर मारने वाला भारत है। यह कथन सिर्फ शब्द नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत की डिफेंस डॉक्ट्रिन का बयान है कि हम आत्मरक्षा के साथ-साथ निर्णयक कार्रवाई की नीति अपनाते हैं।

एक औद्योगिक परियोजना नहीं है, बल्कि यह स्थानीय रोजगार, आत्मनिर्भरता और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह टेक्सटाइल पार्क मेंके इन इंडिया और लोकल फॉर्म ग्लोबल के विज़न को साकार करेगा। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी और करोड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

‘शिक्षा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सपना’: प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी याद दिलाया कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक शिक्षित, स्वावलंबी और आत्मगौरव से परिपूर्ण भारत का सपना देखा था। उन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, ताकि आने वाली पीढ़ियां तेज गति से प्रगति कर सकें। प्रधानमंत्री का मानना है कि आज का भारत उन्हीं मूल्यों और संकल्पों से प्रेरित होकर विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

**‘हैदराबाद मुक्ति आंदोलन की भी चर्चा’:** प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करते हुए हैदराबाद मुक्ति आंदोलन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसी दिन सरदार पटेल के नेतृत्व में हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। उन्होंने इस दिन को “हैदराबाद लिबरेशन डे” के रूप में मनाने की परंपरा शुरू कर देश की एकता की उस ऐतिहासिक घटना को अमर कर दिया है, जिसे दशकों तक भुला दिया गया था।

**‘विकसित भारत: चार स्तंभों पर खड़ा भविष्य’:** प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विकसित भारत के उस विजन की बात की, जिसे 140 करोड़ भारतीयों ने संकल्प के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने इस संकल्प को चार स्तंभों पर आधारित बताया— नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। इन चार स्तंभों के ज़रिए भारत को एक

**‘भारत अब निर्णायक शक्ति’:** धार में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण एक सामान्य राजनीतिक वक्तव्य नहीं था। यह एक राष्ट्रवादी चेतना, सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास, सैन्य आत्मविश्वास, और ऐतिहासिक सृष्टि के सम्मान का शक्तिशाली समागम था। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण न केवल अतीत की गौरवगाथा को सामने लाता है, बल्कि आने वाले भारत की दिशा और दशा भी तय करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत अब केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति, एक संवेदनशील समाज, और एक दृढ़ राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। धार से गूंजा प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश सिर्फ एक शहर या राज्य के लिए नहीं था, बल्कि यह पूरे भारत के लिए है और शायद इसी को कहते हैं — “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।”

भारत और कनाडा संबंधों में 'नया अध्याय' जोड़ने की दिशा में काम करने पर राजी



**नयी दिल्ली, (भाषा)** विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को कहा कि भारत और कनाडा द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर सहमत हुए हैं, जिसमें आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और उनकी कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रोइन ने नयी दिल्ली में व्यापक मुद्दों पर वार्ता की जिसका मुख्य उद्देश्य 2023 में एक सिख अलगाववादी की हत्या को लेकर हुए राजनयिक विवाद के बाद गंभीर तनाव से गुजर रहे द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना था। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को वार्ता के व्यापक परिणामों की जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, “दोनों पक्ष आगे बढ़ने के रास्ते पर मिलकर काम करने और द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने की दिशा में सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर सहमत हुए।” प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जून में कनाडा के कनैनिरिक्स में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के साथ बातचीत की थी। बयान के मुताबिक, बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-कनाडा संबंधों में स्थिरता बहाल करने के लिए ‘रचनात्मक’ कदम उठाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने डोभाल-ड्रोइन वार्ता पर कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष कार्नी के बीच हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने का भी एक अवसर था। इसमें कहा गया है, “दोनों पक्षों ने राजनीतिक नेतृत्व के उच्चतम स्तरों पर विश्वास के पुनर्निर्माण और सहयोग के विस्तार की स्पष्ट गति को स्वीकार किया।” विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर ‘लाभकारी’ चर्चा की, जिसमें आतंकवाद निरोध, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “वे सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने और जुड़ाव के मौजूदा तंत्र को और मजबूत करने पर सहमत हुए।” दोनों एनएसए के बीच यह वार्ता भारत और कनाडा द्वारा एक-दूसरे की राजधानीयों में राजनयिक नियुक्त करने के तीन सप्ताह बाद हुई। भारत-कनाडा के संबंध तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उन आरोपों के बाद चरमरा गए थे जिनमें वर्ष 2023 में हरर्दीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े मामले से भारत का संबंध होने की संभावना जताई गई थी। पिछले साल अक्टूबर में भारत ने अपने उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को तब वापस बुला लिया था, जब ओटावा ने उन्हें निज्जर मामले से जोड़ने की कोशिश की थी। भारत ने कनाडा के भी इतने ही राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था।

ट्रंप ने एच1बी वीजा शुल्क 100,000 अमेरिकी डॉलर करने की घोषणा की, भारतीयों पर असर



**न्यूयॉर्क / वाशिंगटन, (भाषा)** अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाकर सालाना एक लाख अमेरिकी डॉलर किए जाने का प्रावधान है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने “कुछ गैर—आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध” संबंधी घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” है। घटनाक्रम के बाद आव्रजन वकीलों और कंपनियों ने एच-1बी वीजा धारकों और उनके परिवार के सदस्यों से कहा कि अगर वे काम या छुट्टी के सिलसिले में अमेरिका से बाहर हैं, तो अगले 24 घंटों के भीतर वापस आ जाएं, वरना 21 सितंबर की रात 12 बजकर एक मिनट से प्रभावी होने वाले इस फैसले के चलते वे फंस सकते हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। ट्रंप के एच-1बी वीजा शुल्क में बदलाव की घोषणा करने के बाद त्योहारों के लिए स्वदेश जा रहे कई भारतीय पेशेवरों के सैन क्रांसिस्को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान से उत्तरने की खबरें हैं। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के अनुसार, हाल के वर्षों में स्वीकृत कुल एच-1बी वीजा में से लगभग 71 प्रतिशत भारतीयों को जारी किए गए हैं। चीनी इस वीजा कार्यक्रम के दूसरे सबसे बड़े लाभार्थी हैं। फिलहाल एच-1बी वीजा शुल्क नियोक्ता के आकार और अन्य लागत के आधार पर लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर से 5,000 अमेरिकी डॉलर तक है। भारतीय पेशेवरों के बीच बेहद लोकप्रिय ये वीजा तीन साल के लिए वैध होते हैं और इन्हें अगले तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। ट्रंप के फैसले का भारतीय पेशेवरों पर गहरा असर पड़ेगा, जिन्हें प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्र की कंपनियां एच-1बी वीजा पर नियुक्त करती हैं। उद्योग निकाय नैस्कॉम ने शनिवार को कहा कि एच-1बी वीजा आवेदन शुल्क बढ़ाकर एक लाख डॉलर करने के अमेरिका के कदम से भारत की प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि इससे विदेश में चल रही उन परियोजनाओं की व्यावसायिक निरंतरता बाधित होगी, जिनमें समायोजन की जरूरत हो सकती है। नैस्कॉम ने इस बढ़ी हुई राशि को लागू करने के लिए निर्धारित 21 सितंबर की समय—सीमा पर भी चिंता जताई और कहा कि एक दिन की समय—सीमा दुनियाभर के व्यवसायों, पेशेवरों और छात्रों के लिए काफी अनिश्चितता पैदा करती है। अमेरिकी कंग्रेस (संसद) के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि के फैसले को “अमेरिका को उच्च कौशल वाले श्रमिकों से विचित करने का एक लापरवाही भरा प्रयास” करार दिया, जिन्होंने लंबे समय से हमारे कार्यबल को मजबूत किया है, नवाचार को बढ़ावा दिया है और लाखों अमेरिकियों को रोजगार देने वाले उद्योगों के निर्माण में मदद की है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के सलाहकार रह चुके और आव्रजन नीति पर एशियाई—अमेरिकी समुदाय के नेता अजय भुटोरिया ने एच-1बी वीजा शुल्क में वृद्धि संबंधी ट्रंप के फैसले से अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के खतरे में पड़ने की आशंका जताई। भुटोरिया ने कहा, “एच-1बी कार्यक्रम, जो नवाचार के लिए एक जीवनरेखा है और जिसने दुनियाभर से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित किया है, उसे वीजा शुल्क में भारी वृद्धि के चलते अभूतपूर्व बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिससे विविध प्रतिभाओं पर निर्भर छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप बर्बाद हो जाएंगे।”

यूएससीआईएस के मुताबिक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) 2025 में 5,505 स्वीकृत एच-1बी वीजा के साथ अमेजन (एच-1बी वीजा पर 10,044 कर्मचारी) के बाद इस कार्यक्रम की दूसरी सबसे बड़ी लाभार्थी है। यूएससीआईएस के अनुसार, एच-1बी कार्यक्रम के अन्य शीर्ष लाभार्थियों में माइक्रोसोफ्ट (5,189), मेटा (5,123), एप्पल (4,202), गूगल (4,181), डेलोइट (2,353), इंफोसिस (2,004), विप्रो (1,523) और टेक महिंद्रा अमेरिकाज (951) शामिल हैं। ट्रंप ने घोषणापत्र में कहा कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम अमेरिका में ऐसे अस्थायी श्रमिकों को लाने के लिए तैयार किया गया था, जो अतिरिक्त, उच्च-कुशल कार्य कर सकें, लेकिन इसका जानबूझकर दुरुपयोग किया गया, ताकि अमेरिकी श्रमिकों की सहायता करने के बजाय उनकी जगह कम वेतन वाले, कम-कुशल श्रमिकों को नियुक्ति किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “एच-1बी कार्यक्रम का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वीजा धोखाधड़ी, धन शोधन की साजिश और विदेशी श्रमिकों को अमेरिका आने के लिए प्रोत्साहित करने वाली अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल एच-1बी-आधारित आउटसोर्सिंग कंपनियों की पहचान की है और उनकी जांच की है।” ट्रंप ने कहा कि एच-1बी कार्यक्रम का दुरुपयोग रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करने की इच्छुक कंपनियों पर अधिक शुल्क लगाना आवश्यक है, ताकि वे सर्वश्रेष्ठ अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति करें। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ, जो एच-1बी वीजा पर विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, इस नये कदम से चिंतित होंगे, ट्रंप ने कहा कि नहीं, वे “बहुत खुश” होंगे।

एच-१बी वीजा शुल्क बढ़ाने से अमेरिका को भारत से ज्यादा होगा नुकसान: जीटीआरआई  
नयी दिल्ली, (भाषा) अर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने रविवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-१बी वीजा शुल्क बढ़ाकर प्रति कर्मचारी 100,000 अमेरिकी डॉलर करने के फेसले से भारत से ज्यादा अमेरिका को नुकसान होने की संभावना है। 'लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव' (जीटीआरआई) ने बताया कि भारतीय आईटी कंपनियां पहले से ही अमेरिका में 50-80 प्रतिशत स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार दे रही हैं, जो कि कुल मिलाकर लगभग 1,00,000 अमेरिकी नागरिक हैं। जीटीआरआई ने कहा, "इसलिए यह कदम अधिक नए रोजगार नहीं पैदा करेगा। इसके बजाय, यह ॲन-साइट भारतीयों को नियुक्त करना स्थानीय लोगों की तुलना में अधिक महंगा बना देगा।" थिंक टैंक ने आगे कहा कि अमेरिका में पांच वर्षों के अनुभव वाले एक आईटी मैनेजर को 1,20,000 से 1,50,000 डॉलर तक वेतन मिलता है, जबकि एच-१बी वीजा पर आने वाले को इससे 40 प्रतिशत कम और भारत में काम करने वाले को 80 प्रतिशत कम वेतन मिलता है। जीटीआरआई के अजय श्रीवास्तव ने कहा, "इस भारी शुल्क का सामना करते हुए, कंपनियां ॲफशोरिंग को तेज करेंगी, यानी भारत से ही रिमोट वर्क बढ़ेगा। इसका मतलब है कि एच-१बी आवेदन, स्थानीय स्तर पर कम भर्ती, अमेरिकी ग्राहकों के लिए परियोजना लागत में वृद्धि और नवाचार की रफ्तार में कमी।" उन्होंने आगे कहा कि भारत को इस शुल्क वृद्धि का लाभ उठाने की योजना बनानी चाहिए, और लौटने वाली प्रतिभा का उपयोग सॉफ्टवेयर, क्लाउड और साइबर सुरक्षा में घेरेलू क्षमता निर्माण के लिए करना चाहिए, जिससे अमेरिका के इस संरक्षणवादी कदम को भारत के डिजिटल 'स्वराज मिशन' के लिए एक दीर्घकालिक बढ़ावा बनाया जा सके। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप का 19 सितंबर को एच-१बी वीजा शुल्क बढ़ाने का निर्णय भारत से अधिक अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है।" राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिससे कंपनियों द्वारा भारत सहित अन्य देशों से कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वीजा पर शुल्क बढ़ा दिया गया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि एच-१बी वीजा का 1,00,000 डॉलर का शुल्क केवल नए आवेदकों पर लाग होगा।

सरकार ने कारोबारी सुगमता के लिए मंत्रालयों  
को 12,167 एचएसएन कोड आवंटित किए

नयी दिल्ली, (भाषा) सरकार ने नियामकीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा ने के लिए 31 मंत्रालयों और विभागों को 12,167 एचएसएन कोड आवंटित किए हैं। नामकरण की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) कोड के तहत प्रत्येक उत्पाद को वर्गीकृत किया जाता है। इससे दुनिया भर में वस्तुओं के व्यवस्थित वर्गीकरण में मदद मिलती है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को यहां एक कार्यक्रम के दौरान उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा तैयार एचएसएन कोड के मानचित्रण पर मार्गदर्शन पुस्तक का विमोचन किया। इसका मकसद विनिर्माण विकास, निवेश प्रोत्साहन और कारोबारी सुगमता के लिए डेटा आधारित नजरिये को बढ़ावा देना है।

एच1बी मुद्दे पर अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी वित्ती (अपी) अमेरिका का एच1बी मुद्दे पर आपे का सार्वत्र उत्तर

**नया दिल्ली, (भाषा)** भारत सरकार एच1बी मुद्रे पर आग का रास्ता खोजने अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है। सूत्रों ने शनिवार को यह जाना आवेदन शुल्क में वृद्धि अमेरिकी कंपनियों पर और भी ज्यादा असर डालेगी, क्योंकि पेशेवरों के लिए खासतौर से इस वीजा कार्यक्रम का इस्तेमाल करती है। अमेरिकी शुक्रवार को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे एच1बी वीजा आवेदनों को अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा। नियोक्ता के आकार और अन्य लागतों के अलावा अभी तक लगभग 2,000 अमेरिकी डॉलर से 5,000 अमेरिकी डॉलर तक था। सूत्रों ने इस पर आगे का रास्ता निकालने के लिए अमेरिकी सरकार, आईटी उद्योग और रूप से बातचीत कर रही है। सूत्रों ने बताया कि चूंकि अमेरिकी कंपनियां इन वीजों के लिए वे भी इस मामले पर अमेरिकी सरकार के साथ सक्रिय रूप से योगदान कर रही हैं, इसलिए वे भी इस मामले पर अमेरिकी सरकार के साथ सक्रिय रूप से योगदान कर रही हैं। यूएससीआईएस वेबसाइट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 (30 जून, 2025 तक) के अन्तर्गत 10,044 एच-1बी वीजा स्वीकृतियों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। शीर्ष दस टीसीएस (5,505) दूसरे स्थान पर है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प (5,189), एडिसन एंड ब्रॉडकॉम (2,390) और डेलोयट कंसल्टिंग (2,353) का स्थान है। शीर्ष 20 की सूची में इंडिया

जीएसटी कटौतीः साबुन, पाउडर, कॉफी,  
डायपर, बिस्कुट, धी, तेल सस्ते होंगे



तबाकू और अन्य सबाधित वस्तुओं को छाड़कर नहीं कर दरे 22 सिस्टिकर से प्रभावी हो जाएंगे।

**फैदे की व्यापक दृश्यों में कटौती व्योदयी प्रांग**

फुल का व्याज दरा म कठाता, त्याहारा माग,

**वैश्विक चिताओं के बोच सोने में तेजी बनी रहेगी**  
 नयी दिल्ली, (भाषा) वैश्विक मौद्रिक नीतियों में ढील, एशिया में त्योहारी मांग, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और लगातार बने भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण आगामी सप्ताह में सोने की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। विश्लेषकों ने यह जानकारी दी। विश्लेषकों ने कहा कि व्यापारी अमेरिका 2सैन्य भारत के द्वीज द्वारे वार्षीय व्यापार वार्ता<sup>2</sup>में साथ ही वाणिज्य उत्तर और द्वीनिंग के द्वीज

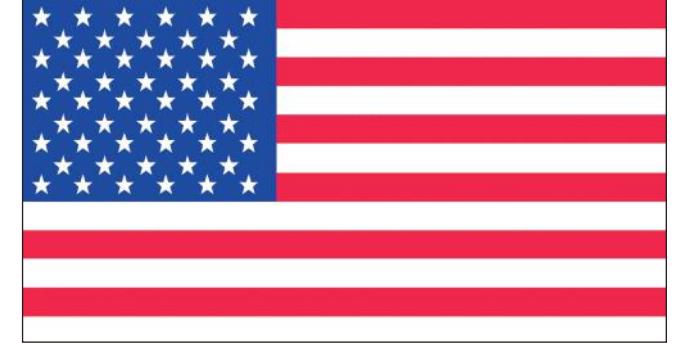
आर भारत के बाच हान वाला आगामा व्यापार वाताआ, साथ हा वाशिंगटन आर बाजग के बाच बातचीत पर बारीकी से नजर बनाए रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा, आवास संबंधी आंकड़े, व्यक्तिगत उपभोग व्यय और उपभोक्ता धारणा जैसे महत्वपूर्ण अमेरिकी वृद्ध आर्थिक आंकड़े बाजार की धारणा को प्रभावित करेंगे। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज में जिस एवं मुद्रा शोध के उपायक्ष प्रणव मेर ने कहा, “एशिया में त्योहारी मांग में मजबूती से सर्रफा को समर्थन मिलने की उम्मीद है,

जबकि ईटीएफ और केंद्रीय बैंक शुद्ध खरीदार बने रहेंगे।

## ईटी उद्योग के साथ बातचीत जारी: सरकारी सूत्र

के लिए आईटी उद्योग और

A horizontal graphic of the United States flag, featuring a blue field with white stars and a red and white striped field.



# How well do you know India's journey towards **#ViksitBharat2047?**

## Test your knowledge with

# THE **VIKSIT BHARAT QUIZ 2026**

& be a part of the nation's transformative journey!

**Visit:**

[QUIZ.MYGOV.IN](http://QUIZ.MYGOV.IN)



## Delhi CM Rekha Gupta hails Sant Rajinder Singh Ji Maharaj as Guiding Light at 29th Global Conference on Mysticism

**New Delhi, Focus News:** World-renowned Spiritual Master and head of Sawan Kirpal Ruhani Mission, Sant Rajinder Singh Ji Maharaj, on Sunday presided over the concluding session of the 29th Global Conference on Mysticism (GCM). He was joined on stage by Hon'ble Delhi Chief Minister Smt. Rekha Gupta Ji, the distinguished Guest of Honour, along with BJP MLA Shri Ashok Goel Ji, Member of Parliament Shri Manoj Tiwari Ji, eminent faith leaders and international delegates. The eight-day global conference, held at Kirpal Bagh, Delhi and Sant Darshan Singh Ji Dham, Burari, Delhi drew tens of thousands of seekers from across India and abroad. The Conference coincided with the birthday of Sant Rajinder Singh Ji Maharaj, also celebrated worldwide as International Meditation Day. In his address, Sant Rajinder Singh Ji Maharaj emphasised the growing need for inner transformation through meditation. "As the 29th GCM comes to a close, it opens before us a path of self-realisation. Each faith has two sides: exoteric (outer) and esoteric (inner). The outer rituals may differ but at its core, every faith points in the same direction — God. It teaches us about finding God through the transformational power of meditation," Sant Rajinder Singh Ji Maharaj said addressing a large gathering. "Just as a teacher imparts worldly knowledge, saints bestow us with inner wisdom. They are the catalytic agents who help us understand our true identity as souls and find God within. Through their own experiences of the Divine, they help us connect with the Divine Light of God, helping us fulfill life's true purpose." The CM hailed Sant Rajinder Singh Ji Maharaj as a "guiding light" and commended the revered Spiritual Master for "showing the path of enlightenment to millions". "It's my great fortune to be here on this auspicious occasion, on the birthday of a true guide," CM said, extending warm wishes to the Spiritual Master. "Sant Rajinder Singh Ji Maharaj's life



beautifully blends science and spirituality. Even after achieving the highest education as a scientist, he chose to serve humanity leading them on the path of spiritual enlightenment, spreading the message of inner peace and selfless service." The Chief Minister sought the blessings of the Spiritual Master, adding that one can only gain in the august presence of such great saints. MLA Shri Ashok Goel Ji praised Sant Rajinder Singh Ji Maharaj for guiding humanity from darkness to Light, commanding his immense contribution to humanity. Shri Manoj Tiwari Ji, said he was drawn by the Spiritual Master's magnetic aura and felt deeply blessed to be in his radiant presence, suggesting that his birthday be celebrated as the sacred "Manifestation Day". The programme commenced with a Gurbani rendition by respected Mata Rita Ji, along with Western delegates, who sang a hymn by Guru Arjan Dev Ji Maharaj, "Koi Bole Ram Ram Koi Khudai (Some call Him, 'Raam, Raam' and some call Him, 'Khuda-i'). Faith leaders and international delegates also shared insights into meditation and spirituality, including M.M. Dr Swami Premanand Ji, M.M. Swami Devendranand Giri Ji Maharaj, Sri Sri Bhagwan Acharya Ji, Rabbi Ezekiel Isaac Malekar, Syed Farid Ahmad Nizami,

Shri Vivek Muni Ji Maharaj, Acharya Yeshi Phuntsok, Father and Deepak Valerian Tauro, USA's Carlos Lozano and Laura Rios of the United Kingdom were the international speakers. Acharya Phuntsok Ji urged the attendees to imbibe the teachings of saints to attain inner peace. Swami Devendranand Giri Ji praised Sant Rajinder Singh Ji Maharaj for spreading peace and love worldwide, while Sri Sri Bhagwan Acharya Ji spoke of his transformative work for humanity. International speaker Lozano said Sant Rajinder Singh Ji has ushered in a "Golden Age of Spirituality". The Conference concluded with the reading of the Declaration by Rabbi Ezekiel, which was unanimously adopted by the participating spiritual leaders. As part of the conference, several humanitarian initiatives were undertaken. The 41st Free Eye Checkup and Cataract Surgery Camp was held at Kirpal Bagh on September 14. On September 20, a Vastra Vitrani Camp was organised to distribute clothes, shoes, books, etc. to the needy. Over the last 35 plus years, Sant Rajinder Singh Ji has provided a blueprint for those who are searching for meaning and purpose of life. He is internationally recognised for his work towards promoting inner and outer peace through meditation and spirituality.

### 28th NATIONAL CONFERENCE ON e-GOVERNANCE BEGINS IN VISHAKHAPATNAM FROM 22ND SEPTEMBER



**New Delhi, Focus News:** The Department of Administrative Reforms & Public Grievances (DARPG) and the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY), in collaboration with the State Government of Andhra Pradesh, are organising the 28th National Conference on e-

Governance (NCeG) 2025 on September 22–23, 2025, in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. The theme for this year's conference is 'Viksit Bharat: Civil Service and Digital Transformation.' The two-day conference will be inaugurated by Shri N. Chandrababu Naidu, Chief Minister of Andhra Pradesh, and Dr. Jitendra Singh, Minister of State (Independent Charge) for the Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth Sciences, Minister of State in the Prime Minister's Office, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Atomic Energy, and Department of Space, Government of India. The two-day event will also be graced by the presence of Shri Pawan Kalyan, Hon'ble Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh and Shri N. Lokesh, Minister for IT, Human Resources Development of Andhra Pradesh. During the conference, the National Awards for e-Governance 2025 will be conferred upon 19 exemplary initiatives. These awards include 10 gold, 6 silver, and 3 jury award across six categories awarded to Central, State, District authorities, Gram Panchayats, and Academic/ Research Institutions. The conference aims to bring together government officials, industry experts, and academicians to discuss innovative and transformative approaches to ensure secure and sustainable e-service delivery in India; thereby contributing to the vision of a Viksit Bharat. The Conference will feature 6 plenary sessions and 6 breakout sessions. Overall, about 70 speakers from diverse backgrounds will share their experiences and present the best practices on a wide range of sub-themes, such as :

Vizag as IT Hub  
AI for Viksit Bharat : Driving Inclusive & Scalable Solutions  
Civil Service and Digital Transformation  
Cybersecurity in e-Governance: Safeguarding Trust, Infrastructure, and Digital Sovereignty  
Benchmarking & Advancement of Service Delivery  
Agri Stack-A Digital Solution for Agriculture  
Excellence in e-Governance Initiatives by Gold Awardees of NAeG 2025-I  
Excellence in e-Governance Initiatives by Gold Awardees of NAeG 2025-II  
Gram Panchayat & Grassroots level Innovations in e-Governance  
e-Governance Initiatives of Government of Andhra Pradesh  
Innovations for Bharat: Catalysts in e-Governance & Digital Empowerment  
International Subsea Cables and AI Data Centres as a Backbone for e-Governance

## LEAD Impact Conclave: LG Kavinder calls for Sustainable and Inclusive Development of Ladakh



**Jammu, Focus News:** Lieutenant Governor of Ladakh, Shri Kavinder Gupta, today addressed the LEAD Impact Conclave in Jammu and said that Ladakh has witnessed unprecedented growth since becoming a Union Territory, with the Administration committed to sustainable and inclusive governance. The Lieutenant Governor said that Ladakh's transformation reflects its focus on renewable energy adoption, paperless governance, and modern administrative reforms, making it a model for other States and Union Territories. "Our endeavour is to ensure that Ladakh becomes a benchmark of balanced development, where economic progress is pursued in harmony with our cultural values and sensitive ecosystem," the Lieutenant Governor said. He reiterated that Education, Health, and Tourism remain the foremost priorities of the Administration. "We are committed to providing quality education, strengthening healthcare infrastructure, and promoting tourism as a key driver of livelihood generation, especially for our youth," he said. Speaking on health initiatives, Shri Gupta highlighted the recent launch of the "Swasth Nari, Sashakt Parivar Abhiyaan" campaign, aimed at improving women's health and family well-being through awareness, screening, and timely access to medical facilities. He said that the campaign reflects the Administration's resolve to ensure that every family in Ladakh has access to quality healthcare services. The Lieutenant Governor also stressed the importance of strengthening the cooperative movement in Ladakh. "Our Administration is working to promote cooperatives, empower Self-Help Groups, and connect local producers with wider markets, thereby creating sustainable livelihoods and ensuring that the benefits of growth reach every household," he said. Referring to Ladakh's identity, Shri Gupta said that Pashmina is our pride, and with the GI Tag, artisans—particularly women—are gaining recognition and building better incomes.

Commending the spirit of the conclave, the Lt Governor said that such platforms bring together citizens, NGOs, businesses, and institutions to work collectively for the region's growth. "We will not just make plans but implement them. We will turn ideas into action and make Ladakh a land of hope and opportunity where development is inclusive, modern, and environmentally responsible," the Lieutenant Governor concluded. Social entrepreneurs, civil society members, and representatives from diverse sectors attended the conclave and expressed their commitment to Ladakh's progress.

## On the occasion of Seva Parv, KVIC launches the grand Khadi Mahotsav 2025



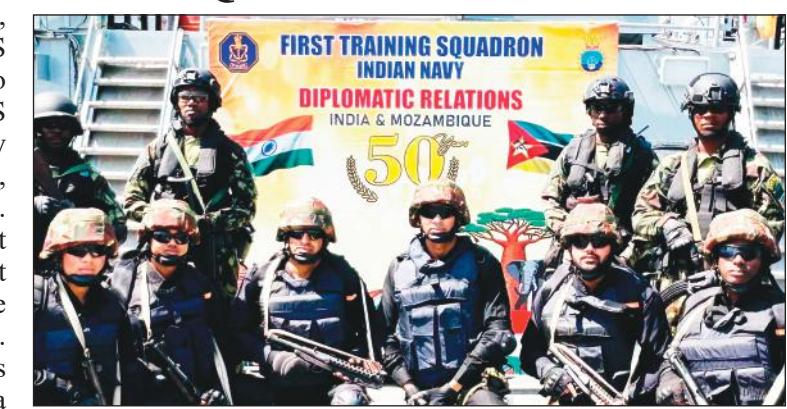
**Mumbai, Focus News:** On the occasion of Seva Parv, the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) is organizing Khadi Mahotsav 2025 across the country from 17th September to 23rd October to promote the message of "Har Ghar Swadeshi, Ghar-Ghar Swadeshi" to every household. On 17th September, KVIC Chairman Shri Manoj Kumar inaugurated Khadi Mahotsav 2025 from the Prime Minister Shri Narendra Modi's parliamentary constituency, Varanasi. Following this, on 18th and 19th September, KVIC's Central Office in Mumbai hosted a series of programs connecting Swadeshi, cleanliness, and self-reliance with people's participation. As part of Seva Parv 2025, a special Cleanliness Drive-05 was organized at Juhu Beach, Mumbai, on 18th September. The campaign was piloted by KVIC Chairman Shri Manoj Kumar, who gave the message of "Serv the Nation by cleanliness". He urged officials, employees, and local citizens to actively participate in building a clean and green India. Hundreds of KVIC officials and employees enthusiastically joined the campaign.

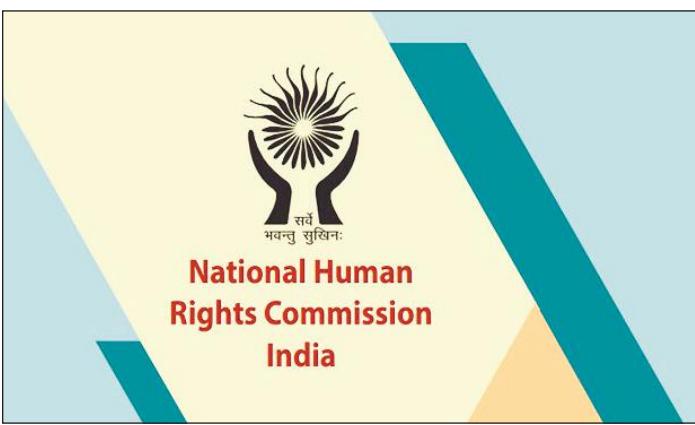
On 19th September, students, employees, and officials who won in various competitions were felicitated with certificates and awards by the Chairman. Addressing the gathering, Shri Manoj Kumar said that with the mantra of "Har Ghar Swadeshi, Ghar-Ghar Swadeshi," KVIC, under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, is carrying the Swadeshi Revolution to every citizen. He further said that inspired by the Prime Minister's call—"Seva hi Sankalp, Rashtra Pratham hi Prerna" (Service is our resolve, Nation First is our momentum)—KVIC is moving ahead on the path of nation's service. Highlighting the importance of Khadi, he said, "Once, famous brands were our priority, but today Khadi has become our priority. Khadi is no longer just a fabric; it is the strong foundation of 'Atmanirbhar Bharat' as envisioned by Mahatma Gandhi." Manoj Kumar also shared that Khadi has now evolved into the true spirit of "Har Ghar Swadeshi" by connecting not just by all the other village artisans from farm to fashion. In the last 11 years, Khadi has transformed significantly, with its business crossing the milestone of ₹1.70 lakh crore. He emphasized that under the guidance of the Hon'ble Prime Minister, KVIC has emerged as strongest pillar of cottage industries, with vigorous efforts to rise Swadeshi to the global stage. Mentioning Prime Minister's words—"We may endure hardships for our nation, but we shall build an Atmanirbhar Bharat"—he reiterated KVIC's commitment.

On this occasion, KVIC's Chief Executive Officer, Ms. Roop Rashi, said that initiatives like 'Seva Parv' and GST benefits are enabling the younger generation to truly understand the values of Khadi and Swadeshi. She remarked that Khadi is not merely a fabric, but a symbol of artisans' dedication and people's collective support, embodying the spirit of self-reliance and cultural identity. She further emphasized that every child can become an ambassador of Khadi. At the Khadi Mahotsav, officers and employees at the Central Office, Mumbai, pledged their commitment to Swadeshi with the spirit of 'Vocal for Local'. Dressed in traditional Khadi attire, they also walked for a 'Khadi Yatra'. In addition, a vibrant Swadeshi Rangoli competition was organized, in which all participated enthusiastically.

## INDIAN NAVY STRENGTHENS TIES WITH MOZAMBIQUE NAVY DURING PORT CALL OF FIRST TRAINING SQUADRON AT MAPUTO

**New Delhi, Focus News:** In a demonstration of enduring maritime friendship, the Indian Navy's First Training Squadron (ITS) comprising INS Tir, INS Shardul, INS Sujata, and ICGS Sarathi concluded its four-day port visit to Maputo, Mozambique from 16-19 Sep 2025. During the deployment, ITS engaged in a series of joint training to enhance operational interoperability with the Mozambique Navy. Activities included Joint Diving Operations, Firefighting, VBSS Ops and Bridge Machinery Control integration drills. Cross-training visit of Indian Navy trainees to Marine Commando School at Katembe, Sargent School at Boane, and the Army Practising School at Manhica fostered mutual understanding and cooperation. Sea riders of the Mozambique Navy embarked onboard ITS ships for joint EEZ surveillance. Capt Tijo K Joseph, Senior Officer of ITS, along with Commanding Officers of visiting ships, paid courtesy calls to Rear Admiral Eugenio Dias Da Silva Muatucu, Chief of the Mozambique Navy; Maj Gen Ezequiel Muianga, Inspector of FADM; Col Candido Jose Tirano, Commandant of Maputo Air Force Base. These high-level interactions underscored the growing defence cooperation between the two nations. Community outreach formed a vital component of the deployment. More than 1,000 school children toured the ships, gaining insights into operational capabilities of the Indian Navy. A medical camp was set up at Naval Headquarters Mozambique and local hospital at Maputo. More than 100 patients were provided medical care and an awareness campaign on prevention of critical disease, emergency response and first aid was conducted.





**New Delhi, Focus News:** The National Human Rights Commission (NHRC), India in collaboration with the Ministry of External Affairs (MEA), is organising a six-day Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Executive Capacity Building Programme on human rights for senior-level functionaries of the National Human Rights Institutions (NHRIs) of the Global South in New Delhi from 22nd to 27th September, 2025. The programme aims to strengthen the capacities of National Human Rights Institutions (NHRIs) from the Global South. This reflects NHRC India's ongoing commitment to global human rights dialogue, South-South cooperation and the collective advancement of rights-based governance. This customised programme has been developed in accordance to the need of NHRIs of participating countries and feedback provided during the three earlier ITEC capacity building programmes organised by the Commission. Senior level functionaries from 12 NHRIs from Mauritius, Jordan, Georgia, Philippines, Qatar, Fiji, Uzbekistan, Bolivia, Nigeria, Mali, Morocco and Paraguay are likely to attend the programme. Drawing from NHRC India's experience of over three decades, the programme seeks to promote deeper understanding, mutual learning and meaningful collaboration among NHRIs for advocacy, enforcement and institutional strengthening across the Global South. Eminent persons with domain knowledge and expertise in capacity building and imparting training will be the resource persons. The programme will be inaugurated by Chairperson of the NHRC, India Justice V. Ramasubramanian. The expected outcome includes developing a better understanding of international dimensions of human rights; a deeper understanding of NHRC, India's work in the field of human rights protection and its best practices, which can be adopted by the other NHRIs; improved networking among NHRIs, fostering collaborations and partnerships at regional and international levels; and enhanced capability to contribute towards the protection and promotion of human rights. The participants will engage in interactive sessions with eminent persons and practitioners in the field, cultural immersion and field visits. This programme stands as a testament to NHRC India's enduring commitment to fostering a world where human rights are respected, protected and celebrated. It aims to serve as a dynamic platform for dialogue, learning and cooperation among NHRIs of the Global South.

### Ministry of Rural Development Signs MoU for Technical Assistance Under DAY-NRLM



**New Delhi, Focus News:** The Ministry of Rural Development signed five Memorandums of Understanding (MoU) with the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR), Hyderabad, and four National Resource Organizations (NROs) i.e. State Rural Livelihoods Missions (SRLMs) of Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, and Telangana—for strengthening interventions under the Deendayal Antyodaya Yojana—National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM). These states have been recognized for their pioneering work in digitisation, with Bihar also leading in Food, Nutrition, Health, and WASH (FNHW) interventions. The MoUs were signed by Shri T.K. Anil Kumar, Additional Secretary (Rural Livelihoods), Ministry of Rural Development with Dr. Vanishree Joseph, Director, NRLM Resource Cell, NIRD&PR; Shri Ananya Mittal, CEO, JSPLS (Jharkhand), and senior officers representing Smt. Karuna Vakati, State Mission Director, Andhra Pradesh SRLM; Shri Himanshu Sharma, CEO, Bihar Jeevika and Ms. D. Divya, CEO, Telangana SERP at NRLM Conference Hall, New Delhi. Through this MoU, which was signed on 19th of this month, the NIRD&PR will focus on building the capacities of SRLM functionaries and community cadres, creating a multi-thematic pool of resource persons, conducting induction and leadership training, and documenting best practices. It will also extend technical and strategic support to strengthen community institutions, enhance livelihood opportunities, promote digital innovations, and deepen social inclusion. This partnership further reaffirms NIRD&PR's role as a national hub for knowledge, training, and innovation in rural development. The Ministry also acknowledged the contribution of National Resource Organizations (NROs), whose technical support has been vital in advancing LokOS, a digital platform developed to improve governance and strengthen seamless operations in Self-Help Groups (SHGs) and their federations. Digitisation through LokOS will enhance accountability and financial integration building self-reliant rural communities through technology.

National Medical Commission Chairman Dr Abhijit Chandrakant Sheth Presides over 11th Convocation Ceremony of Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & Dr Ram Manohar Lohia Hospital



**New Delhi, Focus News:** Dr Abhijit Chandrakant Sheth, Chairman of National Medical Commission presided over the 11th Convocation Ceremony of the Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences (ABVIMS) and Dr Ram Manohar Lohia Hospital, here today. Dr Sunita Sharma, Director General of Health Services (DGHS) and Dr Vinod Kotwal, Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare were also present. Speaking on the occasion, Dr. Sheth congratulated the graduating students as well as their parents and faculty members for their dedication in guiding and motivating the students towards a service in healthcare. He emphasized the government's commitment to increasing the number of doctors in the country to meet the World Health Organization's recommendation of maintaining a uniform doctor-patient ratio of 1:1000 nationwide. Dr. Sheth also shared ongoing efforts to achieve a balanced undergraduate (UG) to postgraduate (PG) ratio of 1:1, aiming to elevate the quality of India's healthcare system to the standards of developed countries. Dr. Sheth also highlighted innovative initiatives being introduced by the National Board of Examinations in Medical Sciences and the National Medical Commission (NMC), such as integrating skill-based and virtual learning alongside traditional physical education, to fulfill the requirements of competency-based medical education. He encouraged the students to prioritize their own health and well-being, to persevere through challenges, and to remain lifelong learners. Dr. Vinod Kotwal emphasized that today's occasion represents the culmination of years of hard work by the students and remarked, "This marks the beginning of your lifelong commitment to the health and well-being of the nation." She also congratulated ABVIMS for its recent NABH accreditation, which "stands as a recognition of the institution's steadfast dedication to quality, safety, and patient-centered care". Dr. Kotwal urged the students to continue pursuing knowledge, discovery, and service with integrity, compassion, and respect as their guiding principles. "Medicine is not just about curing disease; it's about caring for the patients who suffer," she said. Dr. Sunita Sharma, in her address to the graduating students, noted, "You are not merely receiving a degree today; you are shouldering a profound responsibility—to heal, to lead, and to serve the nation in whatever capacity you choose." Whether pursuing clinical care, medical research, or education, she advised, "Let your work be driven by empathy, evidence, and excellence."

Guidebook on Mapping of Harmonized System of Nomenclature (HSN) Codes unveiled by Union Minister of Commerce & Industry Piyush Goyal

**New Delhi, Focus News:** Union Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal, released the Guidebook on Mapping of Harmonized System of Nomenclature (HSN) Codes prepared by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) on 20th September 2025 during the event on "Celebrating 10 Years of Make in India and Discussion on Next Gen Reforms 2.0" in New Delhi. The Guidebook which provides allocation of 12,167 HSN Codes to 31 Ministries and Departments of the Government of India, aims to promote the adoption of data-driven approach for manufacturing development, investment promotion, and trade facilitation. It shall serve as the foundation for building a resilient and competitive manufacturing ecosystem. Emphasizing the significance of this exercise, Shri Goyal mentioned that the Guidebook is a significant stride towards strengthening domestic production capacity and fostering sectoral growth. Additionally, it will also support more effective Trade Agreement negotiations which are aligned with national economic priorities and domain strengths. With the facilitation for identification of the relevant Ministry or Department for specific HSN Codes, this initiative will streamline regulatory processes and further enhance ease of doing business. He added that the Guidebook shall play an integral role in accomplishing the vision of Viksit Bharat by 2047, where governance is responsive to the needs of the industry. The origin of the development of the Guidebook lies in the observation of persistent challenges arising during trade negotiations, import substitution efforts and redressal of industry concerns due to the absence of definitive mapping of HSN Codes. Further, unmapped Codes were



misclassified as 'Residual Products' due to unclear ownership. To address the matter, DPIIT followed a holistic and proactive approach, by undertaking the value-chain and use-case analysis for each of the 12,167 HSN Codes sourced from the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) Tariff Manual. Following this, a thorough review of the Allocation of Business (AoB) Rules, 1961, was done for mapping of each HSN Code based on the nature and end-use of the product. Once the preliminary mapping was completed, several Inter-Ministerial Consultations, multiple Joint Working Group meetings, over 300 one-on-one meetings with Ministries and Departments, and numerous Industry Stakeholder consultations were conducted. The feedback received was systematically analyzed and incorporated to ensure reflection of ground-level realities. The exercise eventually led to the mapping of 12,167 HSN Codes to 31 Ministries and Departments. This extensive and consultative effort culminated in the development of the Guidebook, which now stands as a foundational resource for advancing manufacturing and trade related goals. The Guidebook on Mapping of HSN Codes is a critical enabler for Ministries and Departments to translate policy intent into actionable outcomes.

**A HEALTHY WOMAN = STRONG FAMILY,  
& A STRONG FAMILY = STRONGER NATION**

Take the  
**SWASTH NARI  
SASHAKT  
PARIVAR**

Blood Donation Pledge  
& support women's health, nutrition & care!

**VISIT:  
PLEDGE.MYGOV.IN**

गांधी परिवार ने वायनाड में श्री नारायण गुरु को पुष्पांजलि अर्पित की



## प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में 'नमो युवा रन'



वायनाड (केरल), फोकस न्यूज़, कांग्रेस संसदीय दल की अधिकारी साहिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी बाद्रा ने रविवार को जिले में श्री नारायण गुरु को उनके महासमाधि दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की। तीनों नेताओं ने सुबह कलेपट्टा स्थित श्री नारायण धर्म परिषालन (एसएनडीपी) योगम कार्यालय का लोहा किया और गुरु के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रियंका ने कहा, "हमें श्री नारायण गुरुजी को उन सभी बातों के लिए याद रखना चाहिए, जिसकी अवधारणा, जिसकी समाज में बहुत आधिकारिकता है। हम उन्हें नमन करने के लिए यहाँ आए हैं।" बाद में, प्रियंका ने समस्त केरल जीयत-उल उलेमा के अध्यक्ष सैयद मुहम्मद जिफरी मुथुकोया थांगल से मलप्पुम स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। थांगल ने इसे एक "मैत्रीपूर्ण मुलाकात" बताया और कहा कि प्रियंका ने यह इच्छा जताई थी कि जब भी वह केरल आएंगी तो उनसे अवश्य मिलेंगी। थांगल ने कहा, "पिछले हफ्ते उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैं लिलें के लिए राजी हो गया। मैंने उनसे केरल और पूरे भारत में सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि वह (प्रियंका) और उनका परिवार इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं।" थांगल के अनुसार, प्रियंका ने उनसे कहा कि कांग्रेस पार्टी हमें सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने यह बताया कि उन्होंने प्रियंका को समस्त केरल जीयत-उल उलेमा की गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा, "मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूं, लेकिन मैं नेताओं के समक्ष मुझे उठाता हूं। इसी तरह, मैंने प्रियंका गांधी के समक्ष भी कुछ चिंताएँ रखी।" प्रियंका पिछले 10 दिनों से अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं तथा वायनाड, कोशिकोड और मलप्पुम जिलों के प्रमुख साहित्यिक और धार्मिक हस्तियों सहित मिलने के लिए खड़ी रही है। कांग्रेस सूर्यों ने बताया कि उनका दोरा सोमवार को समाप्त होगा। पार्टी नेताओं ने बताया कि साहिया और राहुल गांधी के भी सोमवार को लौटने की उम्हीर है। वे शनिवार को वायनाड पहुंचे।

सरकार 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कौशल आधारित शिक्षा शुरू करने की योजना बना रही: प्रधान



चेन्नई, फोकस न्यूज़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को यहाँ कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कौशल आधारित शिक्षा को शामिल करने पर विचार कर रही है। प्रधान ने कहा कि उचित स्तर पर शिक्षण पद्धति में आमूलचूल बदलाव होना चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसकी सिफारिश की गई है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में एक कार्यक्रम में कहा, "हम 11वीं और 12वीं कक्षा में कौशल आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने पर काम कर रहे हैं।" प्रधान ने कहा कि उचित स्तर पर शिक्षण के साथ अपनी पूर्ण की बातचीत का जिक्र करते हुए प्रधान ने कहा, "मैं प्रौद्योगिकी आईआईटी-एम निदेशक कामकोटी और उनकी टीम का बहुत आभासी हूं। वे सुयुक्त रूप से विशेष प्रतिभा वाले छात्रों को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें सुविधा प्रदान कर रहे हैं।" बाद में, उन्होंने आईआईटी मद्रास परिसर में छात्रों के साथ ली गई कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि भाषाएं संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निहारती हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी भारतीय कंपनी को किसी इजराली कंपनी के साथ गठजोड़ करना है तो उसे हिन्दू भाषा सीखनी होगी। उन्होंने कहा, "कोई अंग्रेजी या मंदारिन सीख सकता है। हम हिन्दू भी सीख कौशल आधारित शिक्षा है।" उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय छठी कक्षा से ही कौशल आधारित शिक्षा शुरू करने पर भी काम कर रहा है। प्रधान ने कहा, "पहले कौशल आधारित शिक्षा वैकल्पिक थी। लेकिन अब से कौशल एक विषय के रूप में शिक्षा का एक अपवाहिक हिस्सा होगा।" कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षा की पिछली पद्धति सकते हैं। लेकिन अब से कौशल एक विषय के रूप में शिक्षा का एक अपवाहिक हिस्सा होगा।" उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 2047 तक केंद्र के विकासित भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए एक दर्शनीय दस्तावेज है और अगले दो दशकों में एनईपी 2020 की प्रत्येक सिफारिश को लागू किया जाना है।



## गोयल आज व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका जाएंगे

नवी दिल्ली, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर को व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका का दौरा करेगा। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा का मुकाबला दोनों देशों के बीच पारस्परिय व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ावा देने हैं। मंत्री न्यूज़र्ज जाएंगे और उनके साथ मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और अन्य अधिकारी भी होंगे। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों का एक दल 16 सितंबर, 2025 को भारत आया था। इस दौरान व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई थी और इस संबंध में प्रयत्नों को तेज करने का निर्णय लिया गया था। मंत्रालय ने कहा, "इन चर्चाओं के क्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर 2025 को अमेरिका का दौरा कर रहा है।"

Share your ideas & Suggestions with PM for

my  
Gov  
मेरी सरकार

# Mann Ki Baat

on 28<sup>th</sup> Sep 2025

visit [MyGov.in](http://MyGov.in) or Dial 1800 11 7800 (Toll-Free)

The phone lines shall remain open from 5th - 26th September 2025

